भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *317 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 13 मार्च, 2026/22 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है

पंजाब में अंतर्देशीय जल परिवहन

†*317. श्री मलविंदर सिंह कंग :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के रूपनगर जिले में सतलुज नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-98 (एनडब्ल्यू-98) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पंजाब में सतलुज नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन विकास के लिए कोई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली गई है अथवा तैयार की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2016 से उक्त नदी पर घाटों, टर्मिनलों या अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना के लिए स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किन्हीं तकनीकी, जल विज्ञानीय या पर्यावरणीय बाधाओं के कारण उक्त नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास प्रभावित हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पंजाब में किसानों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु 'मैरीटाइम इंडिया विजन' 2030 के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): विवरण, सदन के पटल पर रखा गया है।

"पंजाब में अंतर्देशीय जल परिवहन" के संबंध में माननीय सांसद श्री मलविंदर सिंह कंग द्वारा पूछे गए दिनांक 13.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *317 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): सतलुज नदी, सुन्नी (मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश) में पुल से हरिके बराज (पंजाब) तक राष्ट्रीय जलमार्ग- 98 (रा.ज.-98) के रूप में घोषित किया गया है और यह रूपनगर जिले से भी होकर गजुरता है। सतलुज नदी (रा.ज.-98) का व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट मई, 2026 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ): रा.ज.-98 का व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु 2.82 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है। जलमार्ग अवसंरचना जैसे जेट्टियां, टर्मिनल, तकनीकी, हाइड्रोलोजिकल और पर्यावरणीय बाधाओं आदि के प्रावधान व्यवहार्यता रिपोर्ट का एक भाग होंगे।

(ङ): व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना मैरीटाइम इंडिया विज़न, 2030 के उद्देश्यों के तहत उठाया गया पहला कदम है। व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और किसानों सहित आम जनता के लाभ हेतु विकास संबंधी कार्य किए जाएंगे।

*****